THE

PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT -

IN THE TWELFTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

commencing on the ' i$th February 1956

RAJYA SABHA

Wednesday, 15th February 1956

The House met r.t fifteen minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON THE TABLE

SECRETARY: Sir, I lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 15th February 1956.

राष्ट्रपति (डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद) : संसद् के सदस्यगण, संसद् के इस नये सत्र के समय एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों मामलों की दृष्टि से गत वर्ष हमारे लिए सतत प्रयत्न और सफलता का रहा है। भारतीय जनता और संसद् सकारण विगत वर्ष के प्रयत्नों और सफलताओं को संतोष तथा सतर्क आशा के साथ देख सकते हैं। फिर भी बाहरी जगत में और देश में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटी हैं जिन से हमारा शंकित हो जाना स्वाभाविक है। इन घटनाओं का हमें साहस, धैर्य तथा पूर्ण प्रयत्न के साथ सामना करना चाहिये। साथ ही ये इस बात की चेतावनी भी देती हैं कि हमें न तो निराश होना चाहिये और न पूर्ण संतोष मान लेना चाहिये।

२. विदेशों से हमारे संबंध बराबर मैत्रीपूर्ण बने हैं। गत वर्ष में बहुत से देशों के साथ हमारे सहयोग और सद्भावना में वृद्धि हुई है और इस दिशा में हम जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, विदेशी राष्ट्र अब उसका अधिक आदर करने लगे हैं। बहुत से देशों से इस वर्ष हमारे देश में सम्मानित अतिथि आये, जिन में राष्ट्रों के अधिपति, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हैं। हम ने इन महानुभावों का सहर्ष स्वागत किया। हमारे प्रधान मंत्री ने सरकारी रूप से सोवियत संघ, चैकोस्लवीकिया, पोलैन्ड, औस्ट्रिया, युगोस्लाविया, इटली और मिश्र की सद्भावना-यात्रा की।

३. स्वर्गीय महामहिम महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, नेपाल नरेश की मृत्यु से हमें भारी वेदना हुई। उनके निधन से हमारा देश एक सच्चे मित्र और नेपाल एक प्रबुद्ध तथा साहसी नरेश से वंचित हो गया है। हाल ही में महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाह तथा महिष्मती समाज्ञी के इस देश में आगमन से भारत [illegible] के लोगों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी [illegible]ढ़ हो गये हैं। मैं यह कामना करता हूं [illegible]मामहिम का राज्यकाल उन्नति तथा संपन्नता का सूचक हो।

४. भारत तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच रेलमार्ग खोलने और भारत तथा पाकिस्तान के

मध्य पारपत्र संबंधी नियमों को अधिक ढीला करने के लिये पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत सफल रही हैं। नहर के पानी के संबंध में झगड़ों का निपटारा करने के लिये बातचीत अभी भी जारी हैं। स्थानान्तरित लोगों की चलसंपत्ति के संबंध में समझौता हो चुका हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से लोगों की निकासी और उनका भारत में आगमन हाल में बहुत बढ़ गया हैं, जिस से हमें चिन्ता होती हैं। यह एक बहुत बड़ी मानवीय समस्या हैं जिसका असंख्य लोगों पर दुखद प्रभाव पड़ता हैं। पश्चिम बंगाल राज्य पर आगे ही अत्यधिक भार हैं, अब उसे और भी अधिक भार वहन करना पड़ रहा हैं। मेरी सरकार बराबर आशा करती रहेगी कि पाकिस्तान की सरकार उन कारणों को दूर करने के लिये यथोचित कार्यवाही करेगी जिनके कारण यह निकासी हो रही हैं।

५. मेरी सरकार को दुख हैं कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिये हमारे शांतिपूर्ण सुझावों के बावजूद, पुर्तगाल सरकार की ओर से कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई और वह सरकार दमन और आतंक की उपनिवेशवादी नीति का बराबर आश्रय ले रही हैं। मेरी सरकार को इस बात का बहुत क्षोभ हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सचिव ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए पुर्तगाली बस्तियों को पुर्तगाल के प्रान्त कहा जिससे इस बात का भ्रम होता हैं मानों वे बस्तियां पुर्तगाल देश का एक अंग हों।

६. एशिया और अफ्रीका के देशों का जो सम्मेलन बान्डुंग में हुआ था, जिस में २९ राष्ट्रों ने भाग लिया, उसका स्वागत न केवल एशिया में एक महान घटना के रूप में किया गया बल्कि उसे संसार की एक महत्वपूर्ण घटना माना गया हैं। बान्डुंग में जो ऐतिहासिक महत्व की घोषणा हुई और जिसकी ओर विश्व का काफी ध्यान गया हैं, उसके अनुसार सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों पर यह दायित्व आता हैं कि वे सभी समस्याओं को सुलझाने के लिये और विश्व में शांति और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिये शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और नीति को अपनावें।

७. मेरी सरकार को आशा हैं कि अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट में शीघ्र ही स्वाधीनता और स्वशासन की स्थापना हो सकेगी और वह देश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र में अन्य देशों के साथ बराबर का हिस्सेदार हो सकेगा। पश्चिमी अफ्रीका के अन्य भागों में भी कुछ कुछ इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और मेरी सरकार को आशा हैं कि उन्नति की इस प्रवृत्ति को समुचित प्रोत्साहन मिलेगा और गोल्ड कोस्ट का उदाहरण अफ्रीका के उन भूभागों को भी प्रभावित करेगा जो आजकल औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत हैं। मलाया में भी इसी प्रकार की प्रगति का हम स्वागत करते हैं।

८. हम स्वाधीन तथा स्वतन्त्र गणतन्त्र के रूप में सूडान का स्वागत करते हैं और इस प्रक्रिया में मिश्र तथा बिटेन ने जो महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक योग-दान दिया हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरी सरकार ने सूडान गणराज्य के साथ अन्तःराजनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। मिश्र के साथ भी हमने मैत्री की संधि की हैं।

९. मेरी सरकार ने उन सभी राष्ट्रों के साथ सहानुभूति प्रकट की हैं जो औपनिवेशिक शासन के चंगुल से निकल स्वतन्त्र होने का यत्न कर रहे हैं। उन में विशेष रूप से ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरोक्को की जनता शामिल हैं। मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास हैं कि शांतिपूर्ण बातचीत और आपसी समझौते से ही इन समस्याओं को सफलतापूर्वक और उचित ढंग से सुलझाया जा सकता हैं।

१०. संयुक्त राष्ट्र का हाल का सत्र इस बात के लिए महत्वपूर्ण रहा हैं कि सदस्यता के आधार को अधिक व्यापक करने के संबंध में जो अड़चनें थीं वे दूर हो गई और इस बार सोलह नये राष्ट्र सदस्य के तौर पर स्वीकार किये गये हैं। हमें इस बात

की विशेष खुशी है कि दूसरे देशों के साथ हमारे निकट पड़ोसी, नेपाल और लंका तथा कम्बोडिया, लाओस, लीबिया और जोर्डन भी इन राष्ट्रों में शामिल हैं । हमें इस बात का बहुत दुख है कि जापान और मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए अभी भी उम्मीदवार ही हैं । इस समस्या को सुलझाने का मेरी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी और निकट भविष्य में सूडान के प्रवेश की भी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है ।

११. मेरी सरकार को इस बात का दुख है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा चीन के बीच मत-भेदों को दूर करने के लिए गत वर्ष जो प्रयत्न किये गये थे, और इस दिशा में जो प्रगति हुई थी, वह आगे नहीं बढ़ सकी है । आपसी बातचीत के द्वारा समझौता न होने के जो संभाव्य दुष्परिणाम हैं, वे मेरी सरकार के लिये चिन्ता का विषय हैं। शांतिपूर्ण बातचीत के लिये मेरी सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी ।

१२. इन्डोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने, कुछ दुर्घटनाओं के बावजूद देख-रेख और नियन्त्रण के काम में उचित संतोषजनक प्रगति की है । जेनीवा में महान शक्तियों ने तथा इन्डोचीन से संबद्ध दूसरे पक्षों ने जिन राजनैतिक निपटारों को स्वीकार किया था, वियतनाम के प्रश्न को लेकर वे अब आपत्ति में हैं। लाओस के सम्बन्ध में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । आयोग द्वारा देख-रेख और नियन्त्रण के कार्य पर भी इस समस्या का प्रभाव पड़ा है । मेरी सरकार को आशा है कि सभी संबंधित पक्ष, जेनीवा सम्मेलन के दोनों अध्यक्ष तथा अन्य राष्ट्र इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि न केवल युद्धबन्दी बनी रहे, बल्कि वास्तविक राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सके, जिससे कि उन सभी देशों का कल्याण हो और एशिया की स्थिति अधिक स्थाई हो सके और संघर्ष का संकट, जिसकी सीमाएं सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होतीं, टल सके ।

१३. संयुक्त राष्ट्र से चीन का बहिष्कार और उसके विरुद्ध व्यापार-संबंधी प्रतिबन्ध, सुदूरपूर्व में और साधारणतः एशिया में, अस्थायित्व तथा संघर्ष की ओर प्रेरित करते हैं । मेरी सरकार अन्य राष्ट्रों के सहयोग से, जो हमसे सहमत हैं, संयुक्त राष्ट्र में तथा उससे बाहर इस स्थिति में सुधार करने की अधिक से अधिक चेष्टा करेगी जो स्थिति विश्व-शांति के लिए संभवतः गंभीरतम संकट है ।

१४. सब मिलाकर, गत वर्ष संसार की स्थिति में, विभिन्न गति-विधियों तथा सम्मेलनों, विशेष रूप से चार सरकारों के अध्यक्षों के सम्मेलन, के फलस्वरूप, काफी सुधार हुआ है । मुझे खेद है कि यह प्रगति जारी नहीं रह सकी और इसमें इधर कुछ न्यूनता आई है । निःशस्त्रीकरण के संबंध में वास्तव में हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सके हैं और न ही शीत-युद्ध के भय से उत्पन्न तनाव को दूर कर सके हैं । हमारे देश के अन्य देशों के साथ बराबर मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे किन्तु, विश्वशांति की स्थिति में जो विगाड़ हुआ है उसके कारण दुनियां के दूसरे भू-भागों में भी शांतिपूर्ण संबंधों और पारस्परिक सहयोग की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

१५. शक्ति के संतुलन और आपसी सन्देह और भय पर आधारित सैनिक संधियों की नीति से, विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में, स्थिति बिगड़ी है, जिसके कारण अरब राष्ट्र दलों में बट गये हैं और पश्चिमी एशिया के राष्ट्र शस्त्रास्त्र जुटाने लगे हैं । इसके कारण अपनी सीमाओं के निकट हमें भी चिन्ता हुई है । बगदाद की संधि से भी हमें बहुत अधिक खेद हुआ है, जैसा हमें दक्षिण पूर्व एशिया-संधि-संघ से हुआ था ।

१६. प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि अब समाप्त होने को है और मेरी सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में व्यस्त रही है । पहली योजना की सफलता से लोगों में विश्वास की भावना का उदय हुआ है और उसके परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था की उन्नति की नींव रखी जा चुकी है । पहली योजना के लक्ष्य से कई विषयों में हम आगे बढ़ गए हैं और राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की

वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पत्ति में ४३ प्रतिशत की और कृषि द्वारा उत्पादन में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह विशेष संतोष की बात है कि अन्न का उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ गया है---और यह जबकि विध्वंसकारी बाढ़ ने उत्तर भारत और तूफान ने दक्षिण भारत में बड़ी बरबादी की। इन विपत्तियों के कारण क्षति की पूर्ति में सरकार ने और उससे भी अधिक लोगों ने जो काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूं।

१७. हमारा ध्येय इस देश में समाजवाद के नमूने पर समाज की व्यवस्था करना है और विशेष रूप से उत्पादन को इस प्रकार बढ़ाना है कि देश शीघ्र से शीघ्र समुन्नत हो सके। लोगों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध करने का प्रश्न असाधारण महत्व का है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक विस्तार पर, विशेषकर आधारभूत उद्योगों और मशीनों के निर्माण के उद्योग के विकास पर, अधिक जोर दिया गया है। हमने तीन बड़े लोहे और इस्पात के कारखाने और भारी बिजली कलों के तैयार करने वाले कारखाने खोलने का निश्चय किया है। बड़े पैमाने पर देश के खनिज पदार्थों का पर्यवेक्षण किया जायगा जिससे कि देश में निहित साधनों को उपयोग में लाया जा सके। लोगों को अधिक रोजगार दिलाने और कई प्रकार का उपभोग का सामान पैदा करने की दृष्टि से, उत्पादन की उन विधियों पर अधिक जोर दिया जायगा जिनमें अधिक से अधिक हाथ खप सकें। विशेषकर कुटीर और ग्रामोद्योगों पर भरोसा किया जायेगा। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के फलस्वरूप देश के बहुत से देहातों में पहले ही क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुके हैं। ये योजनाएं बराबर जारी रहेंगी और इन्हें अधिक विस्तृत किया जायगा। आशा है कि द्वितीय योजना की अवधि के अन्त तक इन योजनाओं के अन्तर्गत देश के प्रायः सभी देहात और सभी ग्राम आ चुकेंगे।

१८. दूसरी योजना, प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण है और उसे कार्य रूप देने के लिये देश के लोगों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न करना होगा। समाजवाद के नमूने पर समाज की स्थापना, राष्ट्रीय आय का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर---इन सभी आदर्शों को पूरा करने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना रहता है। परन्तु हम प्रगति के पथ को अपना चुके हैं। हमारी उन्नति के आधारभूत मापदंड सदा समाज का हित और असमता का क्रमिक निराकरण होंगे। हम अपनी यात्रा की एक मंजिल तय कर चुके हैं और अब एक और भाग्य निर्णायक दूसरी मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं। जो सफलता हम ने विगत वर्षों में प्राप्त की है, उससे हमें संतोष होता है, आत्म-विश्वास की भावना प्राप्त होती है और भविष्य के लिये हमारे अन्दर आशा का संचार होता है। किन्तु, उन्नति करने और विश्व में शांति की स्थापना और सहयोग के लिये अपने कर्त्तव्य का पालन करने के हेतु हमारी क्षमता का आधार हमारी आर्थिक दृढ़ता और एकता होगी। राष्ट्रपिता द्वारा निर्धारित मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति हमारी आस्था तथा राष्ट्रीय भावना ही हमारी सफलता की आधारशिला बन सकती है। उस अदम्य राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सेवा की भावना के बिना, जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त कर पाये हैं, हम न उन्नति कर सकते हैं और न ही विश्व के महान कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं।

१९. दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं---दो करोड़ दस लाख एकड़ जमीन की नई सिंचाई, १ करोड़ टन अधिक खाद्यान्न, ३४ लाख किलोवाट नई बिजली, २ करोड़ २० लाख टन कोयले का अधिक उत्पादन, जिस से १९६० तक कुल ६ करोड़ टन उत्पादन हो सके, इस्पात में ३३ लाख टन की वृद्धि, सीमेंट में ५२ लाख टन की वृद्धि और कृत्रिम खाद में १७ लाख टन की वृद्धि। आशा की जाती है कि नई योजनाओं के फलस्वरूप एक करोड़ आदमियों को उद्योग और कृषि में नये काम मिलेंगे।

२०. भारत के कुछ भागों में घटी हाल की घटनाओं से मुझे भारी खेद हुआ है, जैसा कि आप सब को भी हुआ होगा । अपनी भाषा के प्रति उचित प्रेम के अतिरेक में हम में से कुछ यह भूल जाते हैं कि यह महान् देश हम सब की मातृभूमि है और सब के लिए एक जैसी विरासत है । राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए सद्बुद्धि और सहिष्णुता अपेक्षित है, किन्तु भारत और भारत के भविष्य के प्रश्न की तुलना में राज्यों की सीमा-निर्धारण का यह मामला नगण्य है । यह तथ्य सर्वोपरि है कि हम अहिंसा, सहिष्णुता और राष्ट्रीय महानता सूचक मौलिक दृढ़ता के बिना अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते । हाल के वर्षों में हम ने अपने देशवासियों द्वारा प्राप्त की गई अपूर्व सफलताओं को देखा है । हम ने कुछ पुरानी कमजोरियों को अपने मार्ग में आते और पृथकता तथा असहिष्णुता की भावनाओं को उभरते हुए भी देखा है । अतीत में अनेकों बार हमें संकटों का सामना करना पड़ा है और हम ने उन पर विजय पाई है । अब फिर हमारे राष्ट्र और लोगों की परीक्षा का समय आया है । अपने प्राचीन आदर्शों और सिद्धान्तों पर चलकर ही हम सफल हो सकते हैं । मुझे पूरा विश्वास है आप इन बातों पर व्यापक सहिष्णुता की भावना से विचार करेंगे और इस महान् देश के हित को जिसकी हम जी जान से सेवा करना चाहते हैं, सदा सामने रखेंगे । मुझे यह भी आशा है कि यह संसद् जो भी ठीक समझे का निर्णय करेगी, सब लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे ।

२१. जैसा आपको विदित है, भारत के पुराने इंपीरियल बैंक को राज्य बैंक बना दिया गया है और बहुत सोच विचार के बाद मेरी सरकार ने जीवन-बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया है । प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में और पालिसी होलडरों के हितों के रक्षार्थ, गत मास एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके अनुसार इस व्यवसाय की व्यवस्था करने का अधिकार सरकार को दिया गया है । उस अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक संसद् के समक्ष रखा जायगा । निःसन्देह यह पग जनता के और बीमा व्यवसाय के हित में सिद्ध होगा और यह हमारे समाजवादी आदर्श के अनुरूप होगा ।

२२. ग्राम-अर्थ-व्यवस्था और कृषि तथा छोटे छोटे उद्योगों में सहयोग की उन्नति को मेरी सरकार बहुत महत्व देती है । खाद्य-पदार्थों की उत्पत्ति, उनके बनाने और उनको जमा रखने तथा बाजार में लाने के लिये सहयोग समितियों द्वारा उनको संगठित करने का विधेयक संसद् के समक्ष उपस्थित किया जाएगा ।

२३. राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मेरी सरकार एक विधेयक पेश करेगी । संसद् के समक्ष कई विधेयक हैं जिनमें से कुछ पर प्रवर समितियां विचार कर चुकी हैं । पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णयों के अनुसार, परिगणित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन करने के हेतु एक विधान होगा । कर-जांच-आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार पर और आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के सम्बन्ध में भी विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव संसद् के समक्ष रखे जायेंगे ।

२४. तीन अध्यादेश, जो संसद् के गत सत्र के बाद जारी किये गये हैं, संसद् के समक्ष रखे जायेंगे । वे इस प्रकार हैं :

१. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, १९५५,

२. जीवन बीमा (संकटकालीन व्यवस्था) अध्यादेश, १९५६, और

३. बिक्री-कर कानून मान्यता अध्यादेश, १९५६ ।

२५. १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष का भारत सरकार का आय-व्यय-सम्बन्धी विवरण आपके सामने रखा जायेगा ।

२६. इस वर्ष हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह मनाने जा रहे हैं। आज से २,५०० वर्ष पूर्व भारत की एक महानतम विभूति, महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, जिसकी अमर स्मृति और अक्षय सन्देश आज भी विद्यमान हैं। पूर्ण सत्य और शक्ति से ओतप्रोत वह जीवित सन्देश अभी भी हमारे साथ हैं। विश्व के इतिहास में किसी भी समय उस सन्देश की इतनी आवश्यकता नहीं रही जितनी आज हैं, जबकि अणु और उद्जन बमों का भयावह संकट हमारे सामने हैं। मेरी कामना हैं कि महात्मा बुद्ध का सहिष्णुता तथा दया का वह सन्देश आपके सभी कार्यों में आप के साथ रहे।

THE PRESIDENT (DR. RAJENDRA PRASAD): Members of Parliament, I am happy to address you once again and welcome you to the new session of Parliament. The past year has been one of considerable endeavour and achievement for us, both in the domestic and the international spheres. Our people and Parliament may, with reason, look upon them and their own labours with satisfaction and cautious optimism. There have been, however, events at home and abroad, and certain developments which must cause us apprehension. These we must meet with courage, patience and redoubled efforts and remind ourselves that there is room neither for complacency nor for despair.

2. Our relations with foreign countries continue to be friendly. During the year, greater understanding and co-operation have developed with many of them, and there is also increasing appreciation of the approach that we strive to pursue- We have had distinguished visitors from many countries visiting us, including many Heads of States and Governments, Prime Ministers and Foreign Ministers, and we have been happy to,welcome them in our midst. My Prime Minister paid official and goodwill visits to the Soviet Union, Czechoslovakia, Poland, Austria, Yugoslavia, Italy and **Egypt**

3. We were deeply grieved at the death of His Majesty King Tribhuvan Bir Bikram Shah of Nepal, in whom our country nas lost a good friend and Nepal an enlightened and courageous king. The recent visit of His Majesty KinR Mahendra Bir Bikram Shah and his gracious consort has further cemented* the warm and friendly relations between the Indian and Nemlese peoples. I wish His Majesty a progressive and prosperous reign.

4. With Pakistan, negotiations to renew rail traffic between India and West Pakistan and to liberalise the Indo-Pakistan visa system have been successfully concluded, while negotiations in regard to the canal water dispute are being continued. Agreement nas also been reached in regard to moveable property of evacuees.

The exodus of population from East Pakistan ihto India has lately increased/ in numbers and causes us much concern. This is a human problem of great magnitude, with tragic significance to large numbers of people. The State of West Bengal, already heavily burdened, has to shoulder this additional burden. My Government will continue to hope that the Pakistan Government will take appropriate measures to alleviate the circumstances which lead to this exodus.

5. My Government regret that, in spite of our peaceful approach to the solution of the problem of the Portuguese colonies in India, the Portuguese Government have made no response and persist in their methods of colonialism, suppression and terrorism. My Government deeply regret the reference made by the Secretary of State of the United States to **the** Portuguese conquests abroad as 'provinces' of Portugal and the further implication that they.are an integral part of the country of Portugal itself.

6. The Conference of the countries of Asia and Africa at Bandung, at which twenty-nine countries were represented, has been hailed not only as an outstanding event in Asia, **but** is also recognised as one of worm importance. The Bandung Declara-

tion, which is a historic document and to which the world has paid much attention, commits the participating countries to the outlook and policy of peaceful approach for the solution of all problems and far the furtherance of world peace and cooperation.

7. In the continent of Africa, my Government hope that self-government and independence will soon be an established fact in the Gold Coast and that that country will be enabled to become an equal partner both in the Commonwealth and the United Nations. Somewhat similar developments are taking place in some other parts of West Africa, and my Government hope that this progress will gather momentum and that the example will spread to the other parts of Africa now under colonial rule. We welcome also similar developments in Malaya.

8. We welcome the emergence of the Sudan as a free and independent Republic and we pay tribute to the notable and historic part played both by Britain and Egypt in this development. My Government have established diplomatic relations With the Republic of the Sudan. We have also concluded a treaty of friendship with Egypt.

9. My Government have declared their sympathy with the struggles of peoples who strive for their liberation from colonial rule and, more particularly, in respect of the peoples of Tunisia, Algeria and Morocco. It is the firm belief of my Government that in the peaceful approach and negotiations for reaching agreed settlements is alone to be found the right and hopeful way for the solution of these problems.

10. The recent session of the United Nations has been notable for break ing the deadlock in regard to the greater universality of its member ship. Sixteen new nations have been admitted. We are particularly happy that among these are our close neighbours, Nepal and Ceylon, as well as Cambodia, Laos, Libya and Jordan. It is a matter of deep regret, however, that Japan and Mongolia still await entry into that organisation. My Government will use their best endeavours to assist in resolving this problem, and also look forward to the admission of the Sudan in the near future.

11. My Government regret that the progress achieved as a result of the efforts of last year to bring about negotiations and to resolve differences between the United States and China has not made much headway, and observe with concern that the alternative to a negotiated settlement is fraught with grave possibilities. My Government will continue to use their best endeavours to advance the cause of peaceful negotiations.

12. In Indo-China, the work of the International Commissions in regard to supervision and control has been reasonably satisfactory, despite certain incidents. The political solutions agreed to at Geneva by the great Powers, as well as the parties^ concerned in Indo-China itself, however, stand challenged in respect of Vietnam and have encountered serious difficulties in Laos. The Commission ' is confronted with this problem even in its tasks of supervision and control. My Government hope that the parties concerned and the two co-Chairmen of the Geneva Conference, as well as the other powers involved, will use their best efforts not merely to maintain the armistice, but to further real political settlements which will contribute to the welfare of those countries and the stability of Asia and remove the menace of conflict, the bounds of which it is not easy to foresee.

13. In the Far East and Asia generally, the continued exclusion of China from the United Nations and the trade and other embargoes and discriminations imposed against her, make for instability and conflict. My Government will try their utmost, in

common with like-minded governments, both at the United Nations and outside, to help to remedy this situation which continues to be perhaps the gravest threat to world peace.

14. The world situation, as a whole, has shown considerable improvement during the year, as a result of various developments and conferences and notably the Conference of the Heads of four Governments at Geneva. We regret that this progress has not been continued and there has been some deterioration. No actual progress has been made in respect of disarmament or the allaying of the hostilities and fears of the cold war. Our own country continues to have friendly relations with all countries, but this deterioration in the world situation has had adverse results in the development of .peaceful relations and cooperation in our part of the world also.

15. More particularly, the policy of military pacts, based upon balance of power and mutual suspicion and fear, has led to deterioration in Western Asia, created division in the Arab world and resulted in the building up of armaments in Western Asia. This causes us concern even on our near frontiers. We deeply regret the conclusion of the Baghdad Pact as we did that of the SEATO.

16. The period of our first Five Year Plan will soon come to an end and my Government have been actively engaged in preparing the second Five Year Plan. The success of the first Plan has produced confidence in our people and has laid the foundations for a more rapid growth of the national economy. The targets of the first Plan have been in many cases exceeded and the national income has risen by 18 per cent. Industrial production has increased by 43 per cent, and agricultural production by 15 per cent. It is particularly satisfactory that the production of food grains has increased by about 20 per cent., even though there have been disastrous floods in North India and cyclones caused havoc in the south of India. I should like to pay a tribute to the work done by Government, and even more so by the people themselves, in repairing the damage caused by these calamities.

17. Our objective is to establish a socialist pattern of society and, more particularly, to increase the country's productive potential in a way that will make possible progressively faster development. The question of providing more employment is of vital importance. Special stress has been laid on enlarging the public sector and, more especially, on developing basic and machine-making industries. Three new major iron and steel plants and a plant for the manufacture of heavy electrical machinery have been decided upon. It is proposed to carry out mineral surveys on an extensive scale so as to discover and exploit the potential resources of the country. With a view tp creating employment as well as the production of many types of consumer goods, reliance will be placed on labour-intensive methods of production and, more particularly, village and cottage industries. The Community Projects and the National Extension Service have already produced revolutionary changes in many of our rural areas. These will be continued and expanded and, it is hoped, that by the end of the second Plan period, they will cover nearly the whole of our rural area.

18. The second Plan is more ambitious than the first Five Year Plan and involves a far greater effort on the part of our people. We have a long way to go before we reach our objective of a socialist pattern of society and the national income has been raised to an adequate level and there is equal opportunity for all. But we are well set on tbe road to progress. The basic criterion for determining our lines of advance must always be social gain and the progressive removal of inequalities. We have arrived at one stage of our journey and we are now going to embark upon another and more fateful one. The progress we have made during the past years gives us satisfaction and a sense of **self-re-**

liance and hope for the future. But our capacity to progress as well as to make any useful contribution to world peace and co-operation depends upon our economic strength and our unity. It depends on our sense of nationhood and our devotion to the basic ideals and principles which were laid down for us by the Father of the Nation. Without that indomitable sense of national unity and that spirit of dedication to the common cause, which enabled us to achieve independence, we can neither attain progress nor serve the larger causes of the world.

19. The targets of the second Five Year Plan include: new irrigation of 21 million acres, additional 10 million tons of food grains, an increase in power generation by.3˙4 million kilowatts, an increase in the production of coal by 23 million tons so as to reach the target of 60 million tons in 1960, an increase by 33 million tons of finished steel, 52 million tons of cement, and an additional 1-7 million tons of fertilizers. It is expected that as a result of the new schemes, additional employment will be provided for 10 million persons in industry and agriculture.

20. Recent events in some parts of India have caused me great distress, as they must have pained all of you also. In our legitimate love of our languages some of us have forgotten for the moment that this great land is our common heritage and our common motherland. The reorganisation of States is an important matter and we must apply all our wisdom and tolerance to it; but, in the larger perspective of Ind,ia and of India's future, it is a small matter what administrative boundaries we prescribe for a State. Above all, there can be no progress for our country if we do not adhere to non-violence and tolerance and to the basic integrity which makes a people gr.eat. We have witnessed, in recent years, great achievements by our people. We have also witnessed some of our old failings still coming

in our way and encouraging the spirit of separateness and intolerance. Many a time in the past, we have had to face and have overcome severe crises, and again we are on our trial as a nation and as a people. We shall succeed only by adherence to our old principles and ideals. I earnestly trust that you will consider these matters in a spirit of broad tolerance," always keeping in view the greater good of this great country of ours which we cherish and wish to serve. I hope also that, whatever Parliament, in its wisdom, decides will be willingly accepted by all our people.

21. As you are aware, the old Imperial Bank of India has been converted into a State bank and my Government, after careful consideration, have decided to nationalise the life insurance business. As a preliminary step and in order to safeguard the interests of the policy-holders during the interim period, an Ordinance was issued last month vesting in the Central Government the management of life insurance business. A Bill will soon be placed before Parliament to convert this Ordinance into an Act. 1 have no doubt that this step will prove to be in the interests of the public as well as of insurance and will be a step towards the socialist ideal we have before us.

22. My Government attach importance to the reorganisation of rural economy and to the development of co-operatives, both in agriculture and in small-scale industries. Legislation for the purpose of organising agricultural marketing, processing, warehousing and production through cooperatives will be introduced in Parliament.

23. My Government will introduce a Bill in regard to the reorganisation of States. There are a number of Bills pending before Parliament, some of which have been considered by Select Committees. There will be legislation to amend the lists of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the light of the recommendations of the

Backward Classes Commission and their examination by my Government. Legislative proposals in regard to the levy of sales-tax on inter-State transactions and on essential goods, as recommended by the Taxation Enquiry Commission, will also be placed before Parliament.

24. Three Ordinances, which have been promulgated since the last session of Parliament, will be placed before Parliament. These are: —

(1) The Representation of the People (Amendment) Ordinance 1955;

(2) The Life Insurance (Emergency Provisions) Ordinance, 1956; and

(3) The Sales-Tax Laws Validation Ordinance. 1956.

25. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1956-57 will be laid before you.

26. We shall celebrate this year a very significant event. Two thousand five hundred years ago, one of the greatest sons of India, the Buddha, attained *parinirvana* leaving a deathless memory and an eternal message. That living message is with us still in all its truth and vitality. At no time in the history of the world was it needed more than now when we are confronted by the terrible threat of the atomic and hydrogen bombs. May this message of tolerance and compassion of the Buddha be with you in your labours.

PAPERS LAID ON THE TABLE

STATEMENT OF BILLS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT

SECRETARY: Sir, I lay on the Table a statement showing .the Bills passed by the Houses of Parliament during the Eleventh Session, 1955, and assented to by the President:

Statement

1. The Indian Stamp (Amendment) Bill, 1955.
2. The Abolition of Whipping Bill, 1955.
3. The Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Bill, 1955.
4. Th(Appropriation (No. 4) Bill, 1955.
5. The Appropriation /No. 5) Bill, 1955.
6. The Indian Tariff (Second Amendment) Bill, 1955.
7. The Indian Tariff (Third Amendment) Bill, 1955.
8. The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 1955.
9. The Railway Stores (Unlawful Possession) Bill, 1955.
10. The Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Amendment Bill, 1955.
11. The Constitution (Fifth Amendment) Bill, 1955.
12. The Delhi (Control of Building Operations) Bill, 1955.
13. The Insurance (Second Amendment) Bill, 1955.
14. The Press and Registration of Books (Amendment) Bill, 1955
15. The Manipur (Courts) Bill, 1955.
16. The Citizenship Bill, 1955.
17. The Companies Bill, 1955.